रजिस्ट्री सं० डी०ए० ल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3581] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 1, 2019/कार्तिक 10, 1941
No. 3581] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 1, 2019/KARTIKA 10, 1941

India Code

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 2019

का.आ. 3975(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी तीन वर्ष की अवधि के लिए गोवा तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

क्र. सं.	सदस्य	प्रास्थिति
1.	प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग, गोवा सरकार।	पदेन अध्यक्ष;
2.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग गोवा।	पदेन सदस्य;
3.	निदेशक, पंचायत निदेशालय	पदेन सदस्य;
4.	निदेशक, पर्यटन निदेशालय	पदेन सदस्य;
5.	निदेशक, उद्योग व्यापार और वाणिज्य निदेशालय	पदेन सदस्य;
6.	मुख्य इंजीनियर, जल संसाधन विभाग	पदेन सदस्य;

7.	प्रधान मुख्य इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग	पदेन सदस्य;
8.	श्री सेवियो जोआकिम फिलिप कोरिया, न्यूटन अपार्टमैंट-II, मांगोर हिल वास्कोडिगामा	सदस्य (विशेषज्ञ);
9.	श्री फ्लेविआनो जोस मिरांडा, डंकोलिम सराउलिम सेल्सेट गोवा	सदस्य (विशेषज्ञ);
10.	श्री महेश के. पाटिल, विजन पार्क सी एफ एफ 3, टोंका करनजलेम, पंजिम, गोवा	सदस्य (विशेषज्ञ);
11.	श्री सुजीत कुमार मरिअपा डोंगरे, कार्यक्रम समन्वयक, सी ई ई गोवा राज्य, पोरवोरिम, गोवा	सदस्य (विशेषज्ञ);
12.	श्रीरंग वी जम्भाले, ग्राम विकास केन्द्र (एन जी ओ), सेवोएवेरम, गोवा	सदस्य गैर सरकारी संगठन;
13.	निदेशक और पदेन संयुक्त सचिव, पर्यावरण विभाग, गोवा ।	पदेन सदस्य सचिव ।

2. प्राधिकरण का मुख्यालय पोरवोरिम, गोवा में होगा ।

3. प्राधिकरण की बैठक के लिए गणपूर्ति, इसके सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई होगी ।

4. पदेन सदस्य से भिन्न सदस्य को, केंद्रीय सरकार द्वारा नियत मानदंडों के अनुसार भत्तों का भुगतान किया जाएगा ।

5. प्राधिकरण, गोवा राज्य में तटीय पर्यावरण की क्वालिटी को संरक्षित करने और सुधारने तथा तटीय विनिमय जोन क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित उपाय करेगा, अर्थात्:-

(i) प्राधिकरण, परियोजना प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए आवेदन प्राप्ति के पश्चात्, यदि वह अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना के अनुसरण में हैं और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी की गई तटीय विनिमय जोन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) की अपेक्षाओं के भीतर है तो उसका परीक्षण करेगा और संबद्ध प्राधिकरण को ऐसी परियोजना के अनुमोदन के लिए, जैसा कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है, ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर सिफारिशें करेगा;

(ii) प्राधिकरण, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए के अनुसार तटीय विनिमय जोन में सभी विकासात्मक क्रियाकलापों को विनियमित करेगा;

(iii) प्राधिकरण, उक्त अधिसूचना के उपबंधों का प्रवर्तन और मानीटरी के लिए उत्तरदायी होगा;

(iv) प्राधिकरण, तटीय विनिमय जोन क्षेत्रों और तटीय जोन प्रबंध योजना के वर्गीकरण में परिवर्तन या उपांतरणों के लिए राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों की परीक्षा करेगा और राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को उस पर विनिर्दिष्ट सिफारिशें देगा;

(v) प्राधिकरण, उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अभिकथित अतिक्रमण के मामलों में जांच करेगा और उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अतिक्रमण या उल्लंघन को अंतर्वलित करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करेगा;

(vi) प्राधिकरण, उक्त अधिसूचना के अतिक्रमण या उल्लंघन के मामलों में स्वप्रेरणा से या किसी व्यष्टि या निकाय या संगठन द्वारा किए गए परिवाद के आधार पर जांच या पुनर्विलोकन करेगा;

(vii) प्राधिकरण, उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए प्राधिकृत है;

(viii) प्राधिकरण, उसके समक्ष तथ्यों को सत्यापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन यथाअपेक्षित कार्रवाई करेगा ।

6. प्राधिकरण, अपने कृत्यों में पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य के लिए एक समर्पित वेबसाइट तैयार करेगा और इसके कृत्य, जिसके अंतर्गत बैठकों में कार्यसूची, बैठकों का कार्यवृत्त, प्रत्येक बैठक में किए गए विनिश्चय, उक्त अधिसूचना के अतिक्रमण तथा उल्लंघन के मामलों में सिफारिशें और ऐसे अतिक्रमण तथा उल्लंघन पर की गई कार्रवाईयां और न्यायालय मामले जिसके अंतर्गत न्यायालयों के आदेश हैं और राज्य सरकार की अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना से संबंधित सूचना डालेगा ।

7. प्राधिकरण छह माह में कम से कम एक बार अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को भेजेगा ।

[फा.सं. जे-12-6/2005 आईए-III(भाग)]

अरविन्द कुमार नौटियाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

ORDER

New Delhi, the 31st October, 2019

S.O. 3975(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes the Goa Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years, with effect from the date of publication of this order in the Official Gazette, namely:—

Sl.No.	Members	Status
(1)	(2)	(3)
1.	Principal Secretary, Environment Department, Government of Goa	Chairman, *exofficio;*
2.	Principal Chief Conservator of Forest, Department of Forest, Goa	Member, *exofficio;*
3.	The Director, Directorate of Panchayats	Member, *exofficio;*
4.	The Director, Directorate of Tourism	Member, *exofficio;*
5.	The Director, Directorate of Industries, Trade and Commerce	Member, *exofficio;*
6.	The Chief Engineer, Water Resources Department	Member, *exofficio;*
7.	Principal Chief Engineer, Public Works Department	Member, *exofficio;*
8.	Shri Savio Joaquim Filipe Correia, Newton Apartments-II Mangor Hill Vasco-da-gama	Member, (*Expert);*
9.	Shri Flaviano Jose Miranda, Duncolim Seraulim Salcete Goa	Member, (*Expert);*
10.	Shri Mahesh .K. Patil, Vision Park CFF3, Tonca , Caranzalem Panjim Goa	Member, (*Expert);*
11.	Dr. Sujeetkumar Mariapa Dongre, Programme Coordinator, CEE Goa State, Porvorim Goa	Member, (*Expert);*
12.	Shrirang V. Jambhale, Gram Vikas Kendra (NGO) Savoi – Verem Goa	Member, Non-Governmental Organization;
13.	Director and e*xofficio* Joint Secretary, Department of Environment, Goa	Member Secretary, *exofficio.*

2. The Authority shall have its headquarters at Porvorim, Goa.

3. The quorum for the meeting of the Authority shall be one-third of the total number of its Members.

4. A Member, other than an *exofficio* Member, shall be paid allowances as per the norms decided by the Central Government.

5. The Authority shall, for the purposes of protecting and improving the quality of the costal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in the Coastal Regulation Zone areas in the State of Goa, take the following measures, namely:—

(i) the Authority shall, after receiving the application for approval of project proposal, examine the same if it is in accordance with the approved Coastal Zone Management Plan and within the requirements of the Coastal Regulation Zone notification issued by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests and published *vide* number S.O.19(E), dated the 6th January, 2011 (hereinafter referred to as the said notification), and make recommendations for approval of such project to the concerned authority, as specified in the said notification, within a period of sixty days from the date of receipt of such application;

(ii) the Authority shall regulate all developmental activities in the Coastal Regulation Zone areas as specified in the said notification;

(iii) the Authority shall be responsible for enforcing and monitoring the provisions of the said notification;

(iv) the Authority shall examine the proposals received from the State Government for changes or modifications in the classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan and make specific recommendations thereon, to the National Coastal Zone Management Authority;

(v) the Authority shall inquire into cases of alleged violation of the provisions of the said Act or the rules made thereunder; and review the cases involving violations or contraventions of the provisions of the said Act and the rules made thereunder;

(vi) the Authority shall inquire or review cases of violations or contraventions of the said notification suo-moto, or on the basis of a complaint made by any individual or body or organisation;

(vii) the Authority is authorised to file complaints under section 19 of the said Act;

(viii) the Authority shall take such action as may be required under section 10 of the said Act, to verify the facts of the cases before it.

6. The Authority shall, for the purpose of maintaining transparency in its functioning, create a dedicated website and post the information relating to its functions, including the agenda in its meetings, minutes of the meetings, decisions taken in each meeting, recommendations for matters on violations and contravention of the said notification and actions taken on such violations and contraventions, court matters including the orders of the courts and the approved Coastal Zone Management Plan of the State Government.

7. The Authority shall furnish reports of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.

[F. No. 12-6/2005-IA-III (pt)]

ARVIND KUMAR NAUTIYAL, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.11.04 20:00:45 +05'30'